भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1198

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

07 श्रावण, 1943 (शक)

आधार नंबर की पुन: प्राप्ति

1198. श्रीमती रूपा गांगुली:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के बिना आधार नंबर को पुन: प्राप्त करने का कोई अन्य माध्यम है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आधार कार्ड नंबर गुम हो जाने की स्थिति में, कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूआईडीएआई के लिए कोई नागरिक चार्टर हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): जी, हाँ।

I.यदि कोई निवासी अपना आधार नंबर खो देता है/भूल जाता है, तो आधार इकोसिस्टम में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के बिना आधार नंबर खोजने या पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है: -

i) **टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल करना और उन्हें जनसांख्यिकीय विवरण प्रदान करना:** निवासी 1947 पर कॉल कर सकता है और अपना सही जनसांख्यिकी विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, राज्य, जिला, पिन कोड, फोन नंबर आदि प्राप्त कर सकते है। इसे सत्यापित करने के बाद, कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव निवासी को ईआईडी नंबर प्रदान करेगा। एक बार ईआईडी नंबर उपलब्ध हो जाने पर, एक निवासी 1947 पर कॉल करके और ईआईडी नंबर और पिन कोड द्वारा अपना आधार नंबर प्राप्त कर सकता है।

ii) **बायोमेट्रिक डेटा को प्रमाणित करने के लिए आधार नामांकन केंद्र पर जाते हुए**: निवासी आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं और ईआईडी या जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, लिंग, जिला और पिन कोड (अनिवार्य) और जन्म का वर्ष (अतिरिक्त) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ (दोनों मामलों में), प्राप्त कर सकते हैं, निवासी केंद्र से ई-आधार का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकता है।

II. हालांकि यदि मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पंजीकृत है, तो एक निवासी यूआईडीएआई पोर्टल (**https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid**) पर लॉग इन कर सकता है और अपना पूरा नाम और पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जैसे बुनियादी विवरण दर्ज कर सकता है। पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी प्रस्तुत करने पर, यूआईडी नंबर इनपुट के अनुसार पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी पर भेजा जाता है।

(ख): आधार संख्या उपलब्ध नहीं होने या इसे खो जाने की स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियां आधार संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लाभ प्रदान करने के लिए जवाबदेह हैं। इस संबंध में, यह नोट किया जा

सकता है कि आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 7 में सब्सिडी, लाभ या सेवा के वितरण के लिए पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन होने का प्रावधान है। यहां तक कि उन लोगों को भी जिन्हें कोई आधार नंबर नहीं दिया गया है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी सभी अधिसूचनाओं/परिपत्रों में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा आधार नंबर के अभाव के कारण उसे किसी भी सेवा, सब्सिडी या लाभ के वितरण से वंचित नही रखा जाएगा।

विशिष्ट मामलों के संबंध में आधार की आवश्यकता पर अधिक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मिशन ने निम्नलिखित परिपत्र जारी किए हैं:1. "पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में अपवाद हैंडलिंग" पर दिनांक 24.10.17 का यूआईडीएआई परिपत्र 2. "पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में अपवाद हैंडलिंग" पर दिनांक 24.10.17 का खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का पत्र 3. "अपवाद से निपटने" पर दिनांक 19.12.2017 का डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय परिपत्र।

(ग) और (घ): जी, हां। नागरिक चार्टर यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है: **https://uidai.gov.in/images/UIDAI_Citizens_Charter.pdf**

****